नईदुनिया

भोपाल, 2 सितंबर 2026

खास-खबरें

लैपटॉप की फाइलें होंगी अपने आप व्यवस्थित, एक क्लिक में आसान होगा काम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: लैपटॉप में बढ़ती फाइलों को व्यवस्थित रखना अब आसान हो सकता है। एक ऐसा टूल सामने आया है, जो उपयोगकर्ताओं की फाइलों को अपने आप पहचानकर उन्हें सही फोल्डर में व्यवस्थित करने में मदद करता है। इससे फाइल खोजने और उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रखने में लगने वाला समय बचाया जा सकता है।

अक्सर लैपटॉप में काम के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज, फोटो, वीडियो और अन्य फाइलें जमा हो जाती हैं। समय के साथ इन फाइलों को ढूंढना और सही जगह पर रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फाइल मैनेजमेंट टूल उपयोगकर्ताओं के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। यह टूल फाइलों के नाम, प्रकार और अन्य जानकारियों के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटने का काम करता है। उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार नियम तय कर सकते हैं, जिसके आधार पर फाइलें अपने आप संबंधित फोल्डर में चली जाती हैं।

इस तरह बार-बार फाइलों को मैन्युअली व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं पड़ती। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जो रोजाना बड़ी संख्या में दस्तावेजों और डिजिटल फाइलों के साथ काम करते हैं।

22 हजार करोड़ रुपये के कर्ज विवाद पर सुभाष चंद्रा की सफाई

नईदुनिया ब्यूरो, हिसार: जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने 22 हजार करोड़ रुपये के कर्ज विवाद को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी सफाई दी। उन्होंने तीन पन्नों का एक दस्तावेज साझा करते हुए दावा किया कि इस मामले को लेकर गलत धारणाएं और भ्रम फैलाया जा रहा है। सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत उधारी शून्य है। 22 हजार करोड़ रुपये की राशि उनके द्वारा ली गई निजी उधारी नहीं, बल्कि कंपनियों के कर्ज के लिए दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि इस राशि में से केवल 4800 करोड़ रुपये की गारंटी ही कंपनियों द्वारा कर्ज लेते समय दी गई थी, जबकि बाकी गारंटी डिफॉल्ट के बाद जुड़ी। उन्होंने जारी दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि कुल 4808 करोड़ रुपये के कर्ज में से 3803 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और करीब 998 करोड़ रुपये मूल बकाया राशि शेष है। बैंकों की ओर से किए गए कुल दावे में निपटारे के बाद लगभग 4262 करोड़ रुपये का दावा बाकी बताया गया है। यह विवाद तब चर्चा में आया जब कारोबारी विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर एनसीएलटी के फैसले पर सवाल उठाते हुए 22 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर टिप्पणी की थी। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के पर्सनल इंसॉल्वेंसी मामले में उनके रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इसके तहत 22,006.57 करोड़ रुपये के दावे के मुकाबले करीब 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान की योजना को स्वीकृति मिली है। सुभाष चंद्रा ने कहा कि उन्होंने सभी कर्जदाताओं से बातचीत की है और शेष दावों के निपटारे के लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला उनकी व्यक्तिगत उधारी का नहीं, बल्कि कंपनियों के कर्ज के लिए दी गई गारंटी से संबंधित है। मामला वर्ष 2016 में शुरू हुआ था, जब कुछ कंपनियों को दिए गए कर्ज में डिफॉल्ट के बाद व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर सुभाष चंद्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई।

जीडीपी 7.8 प्रतिशत, देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज

आरबीआई के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन, आईटी, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत वृद्धि

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वैश्विक चुनौतियों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में आर्थिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी बढ़कर 81.36 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 75.46 लाख करोड़ रुपये थी। वहीं वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 8.2 प्रतिशत बढ़कर 73.82 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। मौजूदा कीमतों पर आधारित नाममात्र जीडीपी में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 88.27 लाख करोड़ रुपये रही। वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, सूचना प्रौद्योगिकी और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इन

क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन का असर कुल आर्थिक वृद्धि पर दिखाई दिया। सरकार के अनुसार, घरेलू मांग और निवेश में मजबूती के कारण वैश्विक दबावों के बावजूद अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी रही।

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीडीपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया भर के संकटों और तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत ने पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। उन्होंने इसे देशवासियों की क्षमता और मजबूती का परिणाम बताया। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे महंगाई का दबाव बढ़ा है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस चुनौती के बीच भी मजबूत प्रदर्शन किया है। मंत्रालय ने हाल ही में जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 अपनाते हुए नई श्रृंखला जारी की है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गणना के लिए नई पद्धति के साथ जीएसटी नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस और घरेलू सेवाओं से जुड़े आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। इससे आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक आकलन करने में मदद मिलेगी।

जमाखोरी रोकने और त्योहारों से पहले कीमतें नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार का फैसला

चीनी का 2000 क्विंटल स्टॉक रख सकेंगे व्यापारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए डीलर्स के स्टॉक की सीमा तय कर दी है। खाद्य मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, 15 सितंबर से देशभर में चीनी व्यापारी और डीलर्स अधिकतम 2000 क्विंटल तक ही चीनी का भंडारण कर सकेंगे। यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीलर्स को चीनी मिलने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी स्थान पर एक समय में 2000 क्विंटल से ज्यादा चीनी रखने पर रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना है, जिससे बाजार में चीनी की नियमित आपूर्ति बनी रहे और आम उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी मिल सके।

कोलकाता के लिए स्टॉक

सीमा में राहत दी गई है। वहां पहले की तरह 4000 क्विंटल तक चीनी रखने की अनुमति जारी रहेगी।

सरकार के अनुसार, कोलकाता में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी पहुंचती है और यहीं से पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में इसकी आपूर्ति की जाती है। सरकार ने चीनी मिलों, डीलर्स और व्यापारियों के गोदामों की निगरानी भी बढ़ा दी है। गोदामों के भौतिक सत्यापन के दौरान कई जगह अनियमितताएं और अघोषित स्टॉक मिलने की जानकारी सामने आई है।

खुदरा बाजार में भी चीनी के दाम कम होने लगे

सरकारी कार्रवाई और बाजार में बेहतर आपूर्ति के कारण चीनी की थोक कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक गिरावट आई है। इससे खुदरा बाजार में भी चीनी के दाम कम होने लगे हैं। आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी मिलने की उम्मीद है। चीनी उत्पादन को लेकर भी सरकार सतर्क है। उत्पादन में कमी, घरेलू मांग में बढ़ोतरी और सीमित स्टॉक के कारण बाजार में आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई थी। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं, कुछ बड़े रिटेल स्टोरों ने भी ग्राहकों के लिए चीनी खरीद की सीमा तय की है। इसका उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराना और अनावश्यक भंडारण को रोकना है।

सरकार 35 रुपये किलो बेच रही प्याज, 19 शहरों में बढ़ाई बफर स्टॉक की सप्लाई

सरकार बफर स्टॉक से चरणबद्ध तरीके से कर रही प्याज की सप्लाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने नासिक से 'कांदा एक्सप्रेस' के जरिए आ रहे प्याज के बफर स्टॉक को चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। देश के 19 प्रमुख शहरों में 35 रुपये किलोग्राम की दर से प्याज बेचा जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और त्योहारी सीजन से पहले उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज को चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए 'कांदा एक्सप्रेस' और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक से प्याज को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है। प्याज की व्यापक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 30 से भी अधिक ट्रक भेजे गए हैं, जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रखे गए प्याज के बफर स्टॉक से आपूर्ति 24 अगस्त से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के जरिए से शुरू हुई है। इसके तहत नासिक से कांदा एक्सप्रेस की दो खेपें भेजी गई हैं। इसमें 450 मीट्रिक टन प्याज की पहली खेप 27 अगस्त को देर रात नई दिल्ली पहुंची। इसमें से 140 मीट्रिक टन प्याज वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में और बाकी बचा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वितरित किया गया।

एचडीएफसी बैंक की कमान संभाल सकते हैं दिनेश कुमार खारा, सीईओ पद के लिए नाम चर्चा में

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को एचडीएफसी बैंक की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में लंबे अनुभव वाले दिनेश कुमार खारा ने एसबीआई में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में एसबीआई ने डिजिटल बैंकिंग, कारोबार विस्तार और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एचडीएफसी बैंक में नए नेतृत्व की तलाश ऐसे समय में हो रही है, जब बैंक अपने कारोबार को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र के इस प्रमुख बैंक में एमडी और सीईओ पद के लिए अनुभवी बैंकिंग विशेषज्ञ की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रिलायंस ने खरीदा 350 करोड़ में लुटियंस का बंगला

पृथ्वीराज रोड स्थित संपत्ति का उपयोग कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस के रूप में होगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी से जुड़ी रिलायंस समूह की एक कंपनी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित लुटियंस बंगला जोन में पृथ्वीराज रोड पर करीब 350 करोड़ रुपये में एक आलीशान बंगला खरीदा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस संपत्ति का उपयोग अंबानी परिवार के निजी आवास के रूप में नहीं किया जाएगा।

रिलायंस के अनुसार, पृथ्वीराज रोड स्थित इस बंगले को दिल्ली आने वाले कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के ठहरने के लिए कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सौदा जुलाई के अंतिम दिनों में करों के अतिरिक्त करीब 36.7 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 350 करोड़ रुपये में पूरा हुआ।

इस संपत्ति के विक्रेता सिंगापुर के उद्योगपति डॉ. भूपेंद्र कुमार मोदी, जिन्हें बीके मोदी के नाम से जाना जाता है, हैं। रिपोर्टों में इस खरीदारी को रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनी और अनंत अंबानी के फैमिली ऑफिस से संबंधित बताया गया है। हालांकि, रिलायंस ने सौदे में फैमिली ऑफिस की प्रत्यक्ष भूमिका और भुगतान से जुड़े विवरणों पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था के उद्देश्य से यह संपत्ति खरीदी गई है। लुटियंस बंगला जोन में निजी संपत्तियों की खरीद-बिक्री अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण इस सौदे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लुटियंस दिल्ली देश के सबसे प्रतिष्ठित और सुरक्षित इलाकों में शामिल है। इस क्षेत्र की योजना ब्रिटिश शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। चौड़ी सड़कों, विशाल बंगलों और बड़े बगीचों के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में देश के प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कई बड़े उद्योगपतियों के आवास स्थित हैं।

संपत्ति बेचने वाले डॉ. भूपेंद्र कुमार मोदी भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के शुरुआती दौर के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी के कारण उन्हें जॉइंट वेंचर किंग के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने जेरॉक्स, अल्काटेल, ओलिवेट्टी और टेल्स्ट्रा जैसी कंपनियों के साथ व्यावसायिक साझेदारियां कीं। उनकी कंपनी मोदी टेल्स्ट्रा ने वर्ष 1995 में भारत में सेल्युलर मोबाइल सेवाओं की शुरुआत की थी। बाद में स्पाइस ब्रांड भी मोबाइल हैंडसेट बाजार में एक चर्चित नाम बना। बीके मोदी ने बाद में अपना कॉर्पोरेट आधार सिंगापुर स्थानांतरित कर लिया और स्मार्ट ग्रुप के संस्थापक एवं चेयरमैन के रूप में कारोबार से जुड़े रहे हैं।

अगले साल इंसानों से आगे निकल सकता है एआई, मस्क ने जताई आशंका

डिजिटल कामों में बढ़ेगी क्षमता, लेकिन भौतिक कार्यों में इंसानों की जगह लेना अभी संभव नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दुनिया के प्रमुख कारोबारी इलॉन मस्क ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तेजी से इंसानी क्षमताओं के करीब पहुंच रही है। उनका अनुमान है कि अगले साल के अंत तक एआई कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े डिजिटल कार्यों में इंसानों से आगे निकल सकता है। मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एआई की सुपरह्यूमन क्षमता फिलहाल डिजिटल दुनिया तक सीमित रहेगी। फैक्ट्री में उत्पादन या घर बनाने जैसे भौतिक कार्यों में एआई अभी इंसानों की जगह लेने की स्थिति में नहीं है।

मस्क ने कहा कि लोगों को फिलहाल रोबोट आधारित दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में एआई की बढ़ती क्षमता को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई। मस्क ने करीब दस साल पहले गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लैरी पेज ने उस समय चेतावनी दी थी कि भविष्य में एआई कंप्यूटर हैकिंग के मामले में इंसानों से काफी आगे निकल सकता है। एआई खुद कंप्यूटर की कमजोरियों को खोजकर उनका फायदा उठा सकता है। मस्क की यह टिप्पणी वर्सेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुइलेर्मो रोश की उस चिंता के बाद आई, जिसमें उन्होंने इंटरनेट सुरक्षा पर एआई के बढ़ते खतरे की बात कही थी। रोश के अनुसार, एआई एजेंट भविष्य में खुद सिस्टम की कमियां खोजकर साइबर हमले कर सकते हैं। हाल के समय में कई एआई कंपनियों ने अपने सिस्टम से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों की जानकारी दी है। ओपनएआई ने एक सुरक्षा रिपोर्ट में बताया था कि परीक्षण के दौरान उसके कुछ एआई मॉडल ने एक बाहरी सिस्टम को हैक करने की क्षमता दिखाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, कई एआई एजेंट्स ने आपस में बातचीत और सूचनाओं के आदान-प्रदान के दौरान बड़ी मात्रा में संदेश और फाइलें साझा कीं। इसके बाद कुछ एजेंट्स ने एक सिस्टम को निशाना बनाने का प्रयास किया। ओपनएआई के अलावा एंथ्रोपिक और मेटा जैसी कंपनियों ने भी अपने एआई मॉडल्स के अनियंत्रित व्यवहार से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी है।

एआई कैमरों की नजर से बचाएगी खास शर्ट, डिजाइन में छिपा है डिजिटल राज

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एआई आधारित कैमरे जहां लोगों की पहचान और निगरानी करने में तेजी से सक्षम हो रहे हैं, वहीं अब एक खास डिजाइन वाली शर्ट चर्चा में है, जो इन कैमरों को भ्रमित करने का दावा करती है। इस विशेष हवाईयन शर्ट के डिजाइन में डिजिटल छलावरण तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्देश्य एआई कैमरों की पहचान प्रणाली को प्रभावित करना है, जिससे कैमरे व्यक्ति को आसानी से पहचान या ट्रैक न कर सकें। आज के समय में एआई कैमरे सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और विभिन्न डिजिटल प्रणालियों में तेजी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कैमरे चेहरे की पहचान और वस्तुओं को ट्रैक करने जैसी तकनीकों की मदद से लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने ऐसे डिजाइन विकसित करने पर काम शुरू किया है।

पर्पल स्टाइल लैब्स का 680 करोड़ रुपये का आईपीओ खुला

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: आईआईटी बॉम्बे से पढ़े एयरोस्पेस इंजीनियर अभिषेक 'मोंटी' अग्रवाल की कंपनी पर्पल स्टाइल लैब्स का 680 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सोमवार से खुल गया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर मूल्य दायरा 546 से 575 रुपये तय किया है। निवेशक इसमें 2 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। ऊपरी मूल्य स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 4600 करोड़ रुपये आंका गया है। पर्पल स्टाइल लैब्स के संस्थापक अभिषेक अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के बाद उन्होंने डॉयचे बैंक में इक्विटी डेरिवेटिव्स स्ट्रक्चरर के रूप में करियर शुरू किया था।

हालांकि, लग्जरी उत्पादों और फैशन कारोबार में रुचि के चलते उन्होंने वर्ष 2015 में बैंकिंग क्षेत्र छोड़कर फैशन बिजनेस में कदम रखा। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारतीय डिजाइनर ब्रांड्स, तकनीक, रिटेल और वितरण व्यवस्था को एक मंच पर लाना था। वर्ष 2018 में पर्पल स्टाइल लैब्स ने मल्टी-ब्रांड लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म पर्नियाज पॉप-अप शॉप का अधिग्रहण किया, जो कंपनी के विस्तार में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। कंपनी ने मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन क्षेत्र में स्थित इस्माइल बिल्डिंग में भी अपनी मौजूदगी मजबूत की।

यहां अंतरराष्ट्रीय ब्रांड जारा के बंद हुए स्टोर की जगह कंपनी ने अपना विस्तार किया। पर्पल स्टाइल लैब्स में शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर और माधुरी दीक्षित जैसी हस्तियों का निवेश है। कंपनी के पास 1300 से अधिक डिजाइनर्स का नेटवर्क है और यह ऑनलाइन बिक्री के साथ फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से ओम्नीचैनल मॉडल पर काम करती है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का परिचालन राजस्व 13.9 प्रतिशत बढ़कर 557.8 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 489.9 करोड़ रुपये था। हालांकि, विस्तार और निवेश के कारण कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़कर 285.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 188.4 करोड़ रुपये था। कंपनी का ओम्नीचैनल मॉडल ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी को जोड़ता है।

साइबर अपराध

गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने संदिग्ध एपीके फाइलों और खतरनाक एप्स से सावधान रहने की चेतावनी दी

सोशल मीडिया पर फर्जी एप्स से बैंक खातों पर डाका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने का नया तरीका सामने आया है। गृह मंत्रालय की साइबर विंग नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है।

जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडल्ट और पोर्नोग्राफिक कंटेंट से जुड़े फर्जी एप्स के विज्ञापन दिखाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इन विज्ञापनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें एप डाउनलोड

करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने कुछ संदिग्ध एप्स और उनके विभिन्न वैरिएंट्स से दूर रहने की चेतावनी दी है। एजेंसी के अनुसार, साइबर अपराधी आकर्षक और भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। विशेष रूप से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाकर उनके व्यक्तिगत और बैंकिंग संबंधी डेटा तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एडवाइजरी के अनुसार, विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता को एक बाहरी वेबसाइट पर भेजा जाता है। वहां पॉप-अप के माध्यम से एपीके फाइल डाउनलोड करने का विकल्प दिया जाता है। इस तरह डाउनलोड किए गए एप्स सामान्य और विश्वसनीय एप्स की तरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनमें खतरनाक सॉफ्टवेयर छिपे होते हैं। फोन में एप इंस्टॉल करने के दौरान कई उपयोगकर्ता बिना सावधानी बरते विभिन्न परमिशन को मंजूरी दे देते हैं।

एप उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना बैकग्राउंड में अन्य खतरनाक एप्स डाउनलोड कर सकता है

साइबर अपराधी विशेष रूप से फोन की एक्सेसिबिलिटी परमिशन का दुरुपयोग करते हैं। यह अनुमति मिलने के बाद संदिग्ध एप को मोबाइल डिवाइस के कई महत्वपूर्ण कार्यों तक पहुंच मिल सकती है। एक्सेसिबिलिटी परमिशन मिलने के बाद एप उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना बैकग्राउंड में अन्य खतरनाक एप्स डाउनलोड कर सकता है और मोबाइल की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसके जरिए साइबर अपराधी स्मार्टफोन का नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करते हैं। मोबाइल डिवाइस तक पहुंच मिलने के बाद जालसाज बैंकिंग पासवर्ड, अन्य व्यक्तिगत विवरण और ओटीपी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां चुराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बैंक खातों से अनधिकृत रूप से धनराशि स्थानांतरित की जा सकती है। इस तरह की साइबर ठगी में अधिकांश गतिविधियां फोन के बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जिससे उपयोगकर्ता को तत्काल इसकी जानकारी नहीं मिलती। कई मामलों में लोगों को तब ठगी का पता चलता है, जब बैंक खाते से धनराशि कटने का संदेश प्राप्त होता है। गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले संदिग्ध विज्ञापनों, बाहरी वेबसाइटों और अनजान एपीके फाइलों से सावधान रहने की सलाह दी है।